29वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस सम्पन्न, जयपुर डिक्लेरेशन जारी

सुशासन का भविष्य एआइ, लेकिन समझदारी से उपयोग जरूरी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. एआइ सुशासन का भविष्य है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता केवल तकनीक अपनाने में नहीं, बल्कि उसके विवेकपूर्ण उपयोग में है। इसी संदेश के साथ गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआइसी) में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस (एनसीईजी) का समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अप्रासंगिक और पुराने कानूनों को समाप्त कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। डॉ. सिंह ने कहा कि राजस्थान ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन की दिशा में अग्रणी राज्यों में है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा सुझावों, और श्रेष्ठ नवाचारों का अध्ययन कर उपयोगी मॉडलों को राजस्थान के विभिन्न जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कारों के लिए 1.65 लाख ग्राम पंचायतों के साथ विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों से बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए। समापन अवसर पर जयपुर डिक्लेरेशन जारी किया गया तथा साइटेशन बुकलेट, एक्सीलेंस बुकलेट और कंपेंडियम का भी विमोचन किया गया।

पुरस्कार प्रदान करते मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और राज्यवर्धन राठौड़।

17 उत्कृष्ट डिजिटल नवाचार सम्मानित

सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार-2026 प्रदान किए गए। सात श्रेणियों में कुल 17 उत्कृष्ट परियोजनाओं और डिजिटल पहलों को सम्मानित किया गया, जिनमें 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार शामिल हैं। विजेताओं को ट्रॉफी, प्रशस्ति-पत्र के साथ स्वर्ण पुरस्कार के लिए 10 लाख रुपए तथा रजत पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

200 वक्ता, 100 डिजिटल प्लेटफॉर्म

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि दो दिवसीय सम्मेलन में 200 से अधिक वक्ताओं ने डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े अनुभव और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां साझा कीं, जबकि करीब 100 डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी समाधानों का प्रदर्शन किया गया।

एआइ बनेगा 'फोर्स मल्टीप्लायर'

पुलिस जांच होगी तेज, सेवाएं होंगी सुरक्षित

एआइ आने वाले समय में पुलिस की जांच को तेज, स्कूलों की पढ़ाई को और स्मार्ट, सरकारी सेवाओं को घर बैठे अधिक सुरक्षित व आसान बनाएगा। इनमें किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका रहेगी और इसका फायदा किस तरह आमजन तक पहुंचेगा, इस पर विशेषज्ञों ने तकनीकी सत्रों में विस्तार से बात की।

स्मार्ट होगी पुलिसिंग: विशेषज्ञों ने कहा कि एआइ अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपराध रोकने में भी मदद करेगा। आइपीएस गोपेश अग्रवाल ने इसे पुलिस की क्षमता बढ़ाने वाला 'फोर्स मल्टीप्लायर' बताया।

बदलेगी पढ़ाई: देबब्रत नायक ने कहा कि अपार आइडी और डिजिलॉकर से विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी।

सरकारी सेवाएं होंगी और भरोसेमंद: प्रो. वीरेंद्र सिंह ने कहा कि डिजिटल शासन में साइबर सुरक्षा चुनौती है। रवि गुप्ता ने कहा एआइ के प्रभावी उपयोग से सरकारी सेवाएं पारदर्शी, सुरक्षित, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बन रही हैं।